this short banking. An FIR has been lodged with the local police and the matter has also been referred to the CBI by ITDC.

One employee after his arrest by the police has been suspended and against another employee administrative action has been contemplated.

Apprenticeship Training Scheme

2779. SHRI CHATURNAN MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Apprenticeship Training Scheme under the Apprentices Act, 1961 has been implemented in Coal mining industry;

(b) if so, what is the allocation of seats and how many of them have been filled up; and

(c) what are the reasons for the shortfall, if any ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) The located seats are 3, 718. Out of these the seats utilised are 1, 594.

(c) The employers have been reluctant to engage more apprentices than the jobs available, which are also limited due to surplus manpower existing in many of the units. Further the apprentices resort to agitation for absorption in jobs after the completion of training.

Bank Credit Policy

2780. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a,) whether it is a fact that Government have liberalised the bank credit policy;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what categories of persons/firms will be benefited by the above policy and to what extent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Yes, Sir. The following features of the credit policy for the ensuing season announced by Reserve Bank of India are expected to improve the availability of credit;

(i) The banks would continue to be provided expert refinance at 9% per annum and the limits would be equivalent to 100% of the increase in export credit over the monthly average level of credit in 1984. Earlier it has been the practice to keep the preceding year's figures as base for calculating the export refinance limits of banks. The decision to keep base level at 1984 instead of 1985 would result in higher eligibility to the extent of Rs. 200 crores.

(ii) It has been decided that out of the impounded cash balances one-half *i. e.* Rs. 496 crores would be released in two equal instalments on November 22, 1986 and January 31, 1987.

(iii) The banks would be provided with easier access to the discretionary refinance and all licensed scheduled commercial banks (excluding the regional rural banks) would be permitted to draw discretionary refinance without the prior sanction of the Reserve Bank of India, upto an amount equivalent to 0. 5% of the banks' average deposits in 1985-86.

(c) Credit policies are so designed by Reserve Bank of India that all sections of people and all economic activities are benefited. It is not possible to identify any individual group or individual firm separately.

माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन और अभ्रक निर्यातकों के बीच हिस्सेदारी

2781. **श्री कैलाश पति मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन और निजी निर्यातकों के बीच 50:50 के आधार पर हिस्सेदारी की नीति है और प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये का अभ्रक निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक के बाद एक (बैक-टू-बैक) समझौते के अनुक्रम में निर्यातकों ने वर्ष 1985-86 के दौरान माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन को कमीशन तथा सेवा प्रभार के रूप में 1.25 करोड़ रुपये की विशुद्ध आय का भुगतान किया;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्यातकों ने वे आर्डर विदेशों में जाकर स्वयं प्राप्त

किए और अभ्रक के संसाधन की व्यवस्था करने हेतु धन खर्च किया और उन्होंने माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन को करोड़ों रुपये दिए लेकिन उक्त निगम ने 76.00 लाख रुपये का अपव्यय करने के बाद केवल 24.00 लाख रुपये ही आय दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): (क) संसाधित अभ्रक तथा अभ्रक स्क्रेप का निर्यात भारतीय अभ्रक व्यापार निगम (मिटका) के माध्यम से सरणीकृत है मिटका ने निगम द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार मिटकों की ओर से सामान्य मुद्रा क्षेत्र से आर्डर प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व प्राइवेट अभ्रक निर्यातकों को मिटका के एजेंटों को बतौर कार्य करने की सुविधा प्रदान की है, तथापि प्राइवेट निर्यातकों को अपने ही स्रोतों से 50% आर्डरों की व्यवस्था करने के लिए अनुमति है। 1985-86 में संसाधित अभ्रक के कुल निर्यात 24.14 करोड़ रु. के हुए।

(ख) से (घ) 1985-86 के दौरान निर्यात के लिए कुल आर्डरों में से 69% आर्डर मिटका द्वारा स्वयं प्राप्त किए गए तथा 31% आर्डर प्राइवेट निर्यातकों द्वारा लाए गए वर्ष 1985-86 के दौरान प्राइवेट निर्यातकों द्वारा व्यवस्थित बैंक-टू-बैंक संविदा के संघ प्रभारों से 18.60 लाख रु. की आय हुई। किसी भी प्रकार की जांच करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इस संबंध में कंपनी के लेखाओं की संबंधित कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा की जाती है।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम

2782. **श्री कैलाश पति मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना 1972 में की गई थी ताकि वह 2000 छोटे डीलरों से संसाधित अभ्रक निर्यात के लिए खरीदने को सुनिश्चित करे जिससे इन डीलरों और उनके साथ काम कर रहे श्रमिकों का जीवन-यापन होता रहे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम माफिया गैंग को, जिसमें लगभग 200-300 ऐसे डीलर शामिल हैं जिनके पास जाली लाइसेंस हैं और जो सारे लाभों को हड़प रहे हैं; सहायता देता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): (क) से (ग) अभ्रक व्यापार के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के संरक्षण तथा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से आरंभ में 24 जनवरी, 1972 से संसाधित अभ्रक का निर्यात भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि. की मार्फत सरणीकृत किया गया। बाद में 18 जून, 1974 को अभ्रक व्यापार निगम (मिटका) की स्थापना की गई और उसने इन कार्यों को अपने अधिकार में लिया। निर्यात आर्डरों की व्यवस्था करने के लिए मिटका वैध लाइसेंस धारक पंजीकृत व्यापारियों से, जो अपने माल की निविदा देने में स्वतंत्र हैं, माल प्राप्त करता है । संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी अभ्रक व्यापारी लाइसेंसों के आधार पर मिटका व्यापारियों का पंजीकरण करता है। निर्यात के लिए माल प्राप्त करते समय छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाती है।

Banking facilities enjoyed by Thapar Group from Oriental Bank of Commerce

2783. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Oriental Bank of Commerce was owned and con trolled by Thapar group prior to its nationalisation;

(b) what are the banking facilities being enjoyed by the Thapar Group from this Bank at present; and

(c) whether the borrowings of Thapar Group from this Bank are adequately secured as per the norms of the banking sector or any exceptions are made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Prior to its nationalisation, the majority share-holding